सर्व शिक्षक संघ मध्य प्रदेश

स्वागतम्

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को कल तक पैनल तैयार कराने के दिए निर्देश

बारहवीं के विद्यार्थियों को एक्सपर्ट पैनल से वाट्सएप पर मिलेगा हर सवाल का जवाब

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

जिलेवार बारहवीं के प्रत्येक विषय के लिए विषय विशेषज्ञों के समूह तैयार होंगे वाट्सएप ग्रुप पर विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को किया जाएगा हल

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं-बाहरवीं कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर फिलहाल असमंजस बरकरार है। इसी बीच अब विभाग ने 12वीं की परीक्षाएं आयोजित होने के संकेत दिए हैं। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी बेहतर पढ़ाई कर सकें और उन्हें घर पर ही शैक्षणिक समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए जिलों में विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। जिलों को अपने स्तर पर तीन मई तक विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार करनी होगी।

जिलेवार बारहवीं के प्रत्येक विषय के लिए विषय विशेषज्ञों के समूह तैयार होंगे। बता दें कि एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की 30 अप्रैल एवं 1 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को कोरोना के चलते टाल दिया गया है। कोरोना के कारण ऑफलाइन पेपर पेन से जून में भी परीक्षाएं कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है।

हर विषय में कम से कम चार विशेषज्ञों के पैनल

प्रत्येक विषय में कम से कम चार विशेषज्ञों के पैनल बनाए जाएंगे। यह पैनल विद्यार्थियों के प्रश्नों एवं समस्याओं का निराकरण करेगा। इसके लिए वाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमे विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। वाट्सएप ग्रुप पर विद्यार्थी प्रश्न भेजेंगे। जिनका निराकरण विशेषज्ञ करेंगे। किसी के पास जो भी प्रश्न आएंगे वे उन प्रश्नों के जवाब ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि बार-बार प्रश्न का उत्तर फिर न बनाना पड़े।

भोपाल आगे, 40 विषय विशेषज्ञों की टीम तैयार

पैनल बनाने को लेकर भोपाल आगे चल रहा है, यहां 40 विषय विशेषज्ञों की टीम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही वाट्सएप ग्रुप भी बन तैयार हो चुके, जिनमें अब विषयवार बच्चों को जोड़ा जा रहा है।

शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे

अब विद्यार्थियों के पास एक माह का समय शेष है। ऐसे में अब इस एक माह के समय में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। अगर बच्चों को कोई समस्या है तो वह शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए भोपाल जिले में 40 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। सभी के वाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए है और इन ग्रुप में विद्यार्थियों के नंबर जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है।

नितिन सक्सेना
जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

10वीं-12वीं को लेकर मंथन जारी, 9वीं-11वीं का मूल्यांकन कर रिजल्ट हो रहे तैयार

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग कोई निर्णय नहीं ले सका है। वहीं दूसरी ओर 9वीं-11वीं के छात्रों को तिमाही व छमाही परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन शुरू हो गया है। विभाग पंद्रह मई तक रिजल्ट भी जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं।

दरअसल, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने पहले ही कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की मुख्य परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का नवंबर में मूल्यांकन किया गया था। इसमें तिमाही परीक्षा के रूप में रिवीजन टेस्ट व छमाही परीक्षा ली गई थी। अब इन दोनों परीक्षाओं के बेहतर परफार्मेंस के आधार पर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है।

10वीं में नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन मूल्यांकन के मापदंड पर विचार

कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीस अप्रैल से शुरू होने वाली दसवीं की परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग रद्द कर चुका है। अब सिर्फ 12वीं की परीक्षा होगी। दसवीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि दसवीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाए। इस पर हल नहीं निकलने पर सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का विकल्प भी खुला हुआ है।

सीबीएसई ने जारी की अंक निर्धारण नीति

10वीं के छात्रों को मार्क्स देने का फॉर्मूला तय, जून में आएंगे नतीजे

80 अंक पूरे वर्ष के दौरान परीक्षाओं पर आधारित

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर रद्द की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शनिवार को अंक निर्धारण नीति की घोषणा की। वहीं 10वीं बोर्ड का परिणाम जून के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। नीति के अनुसार प्रत्येक विषय में हर साल की तरह 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन जबकि 80 प्रतिशत अंक पूरे वर्ष के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे।

ऐसे होगा मूल्यांकन

यूनिट टेस्ट	10 मार्क्स
हाफ ईयरली एग्जाम	30 मार्क्स
प्री बोर्ड एग्जाम्स	40 मार्क्स

प्राचार्य के नेतृत्व में बनानी होगी 8 सदस्यीय समिति

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान किए गए अंक 10वीं की पिछली बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के प्रदर्शन के अनुरूप हों। स्कूलों को परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में आठ सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। उन्होंने कहा, मूल्यांकन में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने में संलिप्त स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उनकी संबद्धता रद्द कर दी जाएगी।

पत्नी के गहने बेचकर लोगों को बांट रहे फ्री ऑक्सीजन

मुंबई के शख्स ने पेश की मानवता की मिसाल

एजेंसी ● मुंबई

editor@peoplessamachar.co.in

ssmp

कोरोना संकट के गंभीर दौर में कई लोग मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई के मंडप डेकोरेटर पास्कल सल्धाना पत्नी के अनुरोध पर लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं।

पास्कल ने बताया, पत्नी के अनुरोध पर मैंने उसके गहने बेच दिए। उससे हमें 80,000 रु. मिले। उसके बाद मैंने लोगों को फ्री में ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी डायलिसिस और ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। हमारे पास हमेशा एक स्पेयर सिलेंडर होता है। एक स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझसे अपने पति के लिए ऑक्सीजन मांगी। पत्नी के कहने पर एक मैंने उनको दे दिया।

कोर्ट के डर से कुछ अनुकंपा नियुक्तियां कर भूला शिक्षा विभाग

भोपाल। हाईकोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में लगी अवमानना याचिका के चलते स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अगली सुनवाई से पहले धड़ाधड़ नियुक्तियां की गईं। सुनवाई होते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

राज्य शिक्षक संघ ने मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि आश्रितों को सहारा मिल सके। संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि जनवरी, फरवरी में अचानक ही लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश आ गया कि जितने भी अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित हैं, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। बाद में पता चला एक अनुकंपा मामले में अवमानना लगी है, इसीलिए अगली पेशी से पहले ये कवायद की जा रही है। पेशी हुई तो हाईकोर्ट की कार्रवाई से बच गए अब फिर मामला जहां का तहां रुक गया है। यादव ने मांग की है कि नियुक्तियां जल्द से जल्द दी जाएं।

इस सत्र में भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे सरकारी स्कूल,पात्र शिक्षक कर रहे इंतजार

नौकरी● उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। तीन साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है। दो बार जुलाई 2020 में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई। अप्रैल 2021 से फिर से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कोरोना के कारण फिर करीब 50 फीसद अभ्यर्थी अटक गए हैं। उधर, लोकशिक्षण संचालनालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर अतिथि शिक्षकों को रखे जाने का आदेश जारी किया है। इस सत्र में भी सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक पढ़ाएंगे और शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना कम है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सितंबर 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हुए। फरवरी व मार्च 2019 में परीक्षा ली गई। 2020 में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू हुआ, लेकिन जुलाई 2020 में कोरोना के कारण रोक दिया गया। बता दें कि 15 हजार उच्च माध्यमिक और 5670 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होना है। साथ ही विभाग द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के हिसाब से रिक्तियां भी कम निकाली गई हैं।

सात साल बाद हो रही थी भर्ती

2013 में 42 हजार पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी भर्ती 2014-15 में की गई। करीब सात साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई।

शासन को अतिथि शिक्षकों की जगह स्थाई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करनी चाहिए। सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है, लेकिन इस सत्र में भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने की संभावना है।

-रंजीत गौर, प्रदेश संयोजक, मप्र शिक्षक पात्रता संघ

कोरोना के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की जाएगी। जब प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य होगी, तभी प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी, लेकिन कब तक यह तय नहीं है।

-इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री

दसवीं व बारहवीं को छोड़कर बंद कर दी गई ऑनलाइन कक्षाएं

भोपाल। प्रदेश के सभी स्कूलों में शनिवार से ऑनलाइन कक्षाएं 31 मई तक के लिए बंद कर दी गई हैं, जबकि दसवीं-बारहवीं की कक्षाएं चालू रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा, लेकिन राजधानी के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 में विभाग के आदेश की अवहेलना की गई और ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गईं।

कोरोना के चलते बीते एक साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित चल रही है। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले साल 30 जुलाई 2020 से ऑनलाइन क्लास शुरू की थी। निजी समेत सरकारी स्कूलों द्वारा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा से ही पढ़ाया जा रहा था। निजी स्कूलों ने पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली। वहीं सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं के बच्चों की परीक्षा वर्कशीट के माध्यम से घर पर ली गई। इसके बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए। साथ ही अप्रैल के पहले सप्ताह से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से ही नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी गई। अब बच्चों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण उपजे तनाव को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 संक्रमण विस्तार के कारण विद्यार्थियों में भय एवं तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। इसे देखते हुए सभी बोर्ड के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं आगामी एक मई से 31 मई तक संचालित नहीं की जाएगी। हालांकि बोर्ड की परीक्षा के कारण दसवीं-बारहवीं की ऑनलाइन कक्षा पहले की तरह संचालित होती रहेंगी।

बारहवीं के बच्चों के लिए तैयारी

उधर, स्कूल शिक्षा विभाग दसवीं की परीक्षा को लेकर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं कर रहा है। इससे विद्यार्थी असमंजस में है कि परीक्षा होगी कि नहीं। वहीं बारहवी के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों का पैनल गठित कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

10-12वीं की परीक्षा को लेकर असमंजस, 9वीं-11वीं में तिमाही-छमाही से मूल्यांकन

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893232137

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10-12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर असमंजस बरकरार है। ये परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, लेकिन इनके मूल्यांकन को लेकर विभाग निर्णय नहीं ले पाया है।

वहीं 9वीं और11वीं के छात्रों को तिमाही व छमाही परीक्षा के आधार पर नंबर देने और दोनों कक्षाओं के रिजल्ट 15 मई तक घोषित करने के आदेश जारी हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। नवंबर में मूल्यांकन किया गया था। इसमें तिमाही परीक्षा के रूप में रिवीजन टेस्ट व छमाही परीक्षा ली गई थी। इससे दोनों परीक्षाओं के बेहतर परफार्मेंस के आधार पर मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार 9वीं कक्षा के फाइनल परीक्षा परिणाम पांच विषयों में सर्वश्रेष्ठ के आधार पर जारी होंगे। एक से अधिक विषयों में 33 फीसदी अंक पाने में असफल रहने वाले छात्रों के लिए अधिकतम 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। वे छात्र जो नवंबर 2020 या फरवरी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा। यह मौका स्थिति में सुधार के बाद दिया जाएगा।

ssmp

10वीं में जनरल प्रमोशन नहीं: स्कूल शिक्षा विभाग दसवीं की परीक्षा रद्द कर चुका है। सिर्फ 12वीं की परीक्षा होगी। 10वीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। उनके मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है।

परीक्षा पैटर्न पर चल रहा विचार

12वीं की परीक्षा शीघ्र ली जाएगी, उसके पैटर्न पर विचार चल रहा है। 10वीं की परीक्षा निरस्त हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। कई बिंदुओं पर विमर्श चल रहा है। शीघ्र ही 10वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट को लेकर आदेश जारी होंगे।

इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मप्र (स्वतंत्र प्रभार)

सीबीएसई : 10वीं का परिणाम 20 जून को

नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं के छात्रों का परिणाम 20 जून को जारी करेगा। बोर्ड ने इस संबंध में शनिवार को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। 10वीं में इस बार 21.5 लाख बच्चे हैं।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते 10वीं की परीक्षा रद कर दी गई थी। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम को लेकर मूल्यांकन नीति तैयार की है। इसके मुताबिक छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री-बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। 10वीं के प्रत्येक विषय की परीक्षा 100 अंक की होती है। इसमें 20 अंक स्कूल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देता है, जबकि 80 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन के अंक ज्यादातर स्कूलों ने सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए हैं। जिन स्कूलों ने ये अंक अपलोड नहीं किए, उन्हें 11 जून तक करना होगा। बोर्ड के मुताबिक परीक्षाएं रद होने के बाद बचे हुए 80 अंकों का मूल्यांकन भी स्कूलों को ही करना है। इसके लिए स्कूलों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कराई गई परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। इसमें 10 अंक यूनिट टेस्ट, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा और 40 अंक प्री-बोर्ड परीक्षा के होंगे।

नीति तैयार

- यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक और प्री-बोर्ड परीक्षा के अंक के आधार पर मूल्यांकन
- मूल्यांकन पर नजर रखने प्रधानाचार्य के नेतृत्व में गठित की जाएगी समिति

परिणाम तैयार करने के लिए हर स्कूल में बनाई जाएगी समिति

हर स्कूल में परिणाम तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य और सात शिक्षक शामिल होंगे। इसमें पांच शिक्षक विभिन्न विषयों और दो नजदीकी स्कूल के होंगे, वहीं स्कूलों को 25 मई तक परिणाम तैयार कर पांच जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

ssmp

12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी किए

सीबीएसई ने शनिवार को 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी किए, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। मालूम हो कि कोरोना के चलते बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को रद और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। बोर्ड इसकी परीक्षा तिथियां जारी करने के 15 दिन पहले सूचित करेगा।

असहमत छात्र दे सकेंगे परीक्षा

जो छात्र बोर्ड द्वारा किए गए आकलन से सहमत नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि यह उस समय के हालात पर निर्भर करेगा।

बिना किसी आर्थिक बाधा के गरीब और मध्यमवर्ग स्टूडेंट्स ऑनलाइन कर सकेंगे जेईई-नीट की पढ़ाई

यूथ आज के समय में बहुत कुछ नया कर रहा है। उसके अपने प्लान और आइडियाज हैं, जिसे वह स्टार्टअप के रूप में प्रारंभ कर अपने कैरियर को

तो उड़ान दे ही रहा है, साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। स्टार्टअप एमपी के इस कॉलम से जानिए उनके आइडियाज और प्लान...

रितेश सिंह चंदेल
स्टार्टअप
अरिविहान

एप को बनाने में लगे आठ महीने, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं स्टूडेंटस, सभी लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड

● लेक सिटी रिपोर्टर ●

कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते कोचिंग संस्थाएं बंद हो चुकी हैं और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण आज जेईई, नीट जैसी परीक्षा की तैयारी की सालाना फीस बढ़कर लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है और मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवार के स्टूडेंट्स के लिए इतनी फीस भरना आसान नहीं है। इस आर्थिक बाधा के कारण उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मौका नहीं मिल पाता है। इस समस्या का हल निकालने के लिए शहर के रितिक चंदेल ने अरिविहान स्टार्टअप तैयार किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस एप पर सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मशीन लर्निंग और वॉयस एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से यह विडियोज स्टूडेंट्स के सवाल का जवाब देंगे। इससे सभी वर्ग के स्टूडेंट्स बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी परीक्षाओं की उच्च स्तरीय तैयारी कर सकेंगे।

आईआईटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स दे रहे सवालों के जवाब

रितेश कहते हैं कि टीम द्वारा इस अभियान की शुरुआत एक साल पहले ब्राउट बस्टर नाम के एप से की थी। इस एप के द्वारा बोर्ड और कॉम्पीटीटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे फ्री में आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों से जुड़कर अपने सवाल के जवाब पा सकते थे। धीरे-धीरे परेशानियों को समझते हुए ऑटोमेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म अरिविहान को तैयार किया।

स्टार्टअप पर विश्वास दिलाना चुनौती

कई स्टार्टअप आज देश की तरक्की में योगदान कर रहे हैं, लेकिन शहर में स्टार्टअप आइडिया पर काम करना और शुरुआती दौर में दूसरों को स्टार्टअप आइडिया पर विश्वास दिलाना एक चुनौती से कम नहीं था। खुद से सवाल करने वाला और स्टूडेंट्स के जवाब के हिसाब से लेक्चर्स बदलने वाले एप को बनाने में आठ महीने लगे। इसमें कई कठिन टॉपिक्स पर लेक्चर्स हैं और बच्चे मॉक टेस्ट देने के साथ-साथ अपने सवाल के जवाब आईआईटी स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं। जून 2021 तक कक्षा 11वीं और 12वीं के विषय एवं हर टॉपिक के लिए लेक्चर्स पूरी तरह से तैयार हैं।

जवाब के आधार पर कंटेंट बदलने में सक्षम

रितेश कहते हैं कि एप खासतौर पर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया है। यह एप रिकॉर्डेड लेक्चर्स से पढ़ाने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी कि मदद से किसी टीचर की तरह खुद ही बच्चों से सवाल के जवाब देने में और उनके जवाब के आधार पर लेक्चर का कंटेंट बदलने में सक्षम है। रितिक कहते हैं कि अरिविहान एप भोपाल स्थित बी-नेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर के द्वारा इनोनेक्ट चैलेंज में टॉप 10 इनोवेटिव स्टार्टअप में रहा है।

एंकर स्टोरी

प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो ने जारी की अपील

संक्रमण कर रहा अधिक लोगों को प्रभावित, डबल मास्क का करें उपयोग

शहर संवाददाता, भोपाल। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। अनेक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस इस बार अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है और इसके बचाव के लिए हमें डबल मास्क लगाने की आवश्यकता है। अनिवार्य रूप से एक ट्रिपल लेयर अच्छी गुणवत्ता का डबल मास्क का उपयोग करें। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाए। घरों में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने दे। इसके साथ ही आपने घरों से मेडिकल आपात जरूरत के बिना नहीं निकले। यह अपील प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबी) द्वारा जनहित में की गई है।

प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए डबल मास्क का उपयोग करें, यदि हम डबल मास्क पहने, तो हम कोरोना से बचाव कर सकते है। इसके लिए हमेशा एक सर्जिकल और एक कॉटन मास्क पहने। एन 95 के साथ 2 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।

इन लक्षणों को ले गंभीरता से

कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए उसकी चैन को ब्रेक करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी लोग घरों में रहे और घर में किसी को भी सर्दी खांसी, बुखार, आंखो का आना, सर दर्द, पेट दर्द के साथ मरोड़ और पेट खराब होने के लक्षणों को गंभीरता से ले। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही सबसे अलग कर दूसरे कमरे में आइसोलेट कर दे। डॉक्टर से संपर्क कर कोरोना की जांच कराए। घरों के बाकी सदस्य भी लोगो से मिलना जुलना बंद कर दे और फिजिकल डिस्टेंस रखें। सभी लोग घरों में भी मास्क लगाकर रखे और लक्षण वाले मरीज को कोरोना जांच अनिवार्य रूप से कराए।

इनका करें सेवन

लगातार प्राणायाम और योगा करते रहें, मल्टी विटामिन, विटामिन सी, जिंकोविट आदि की गोलियों का सेवन करते रहे, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, हाथों को साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें।

आक्सीजन की सुविधा के साथ मरीजों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचा रहे आटो चालक पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

भोपाल (शाप्र)। आक्सीजन जैसी सुविधा के साथ मरीजों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचा रहे आटो चालक जावेद पर लाकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कराना भारी पड़ गया। छोला थाने में मामला दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस का जबरदस्त विरोध होने के बाद अपराध खारिज कर दिया गया है। जबकि जावेद के लिए एक विशेष पास जारी किया गया है, ताकि उसे लॉकडाउन के दौरान रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़े। ज्ञात है कि इसके पहले भी कोलार में मां को अस्पताल लेकर जा रहे बेटे से पुलिस ने मारपीट कर दी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक बाग फरहत आफजा निवासी जावेद खान ने अपने ऑटो रिक्शा को ऐंबुलेंस बनाकर मरीजों की सेवा शुरू की है। जावेद ने बताया कि शनिवार सुबह एक भानपुर से एक मरीज को सीटी स्केन कराने के लिए ले जाना था। मरीज को ऑक्सीजन की भी जरूरत थी। जावेद मरीज को लेने जा रहे थे, तभी भानपुर पर छोला मंदिर पुलिस ने उसे रोक लिया। जब उसने मरीज की गंभीर हालत का हवाला देते हुए जाने की अनुमति देने को कहा, तो पुलिस उसे ऑटो सहित थाने ले आई। घटना के बारे में पता चलते ही सोशल मीडिया में पुलिस कार्रवाई की जमकर आलोचना का दौर शुरू हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने माना कि जावेद भी कोरोना वारियर है। इसके बाद शाम को उसके खिलाफ धारा-188 के तहत दर्ज किए गए अपराध को खारिज कर दिया गया है।

ssmp

10वीं और 12वीं के प्रवेश-पत्रों में 10 मई तक करा सकेंगे संशोधन

ssmp

जागरण सतना। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वोकेशनल और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश-पत्रों में अब विद्यार्थी 10 मई 2021 तक संशोधन करा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 15 अप्रैल निर्धारित थी।

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा स्थगित

जागरण सतना। राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति के लिए 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओ. एल. मंडलोई ने बताया कि एनएमएसएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पूर्व में 15 अप्रैल थी, जिसे 15 मई 2021 तक बढ़ाया गया है। इच्छुक छात्र एमपी-ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की है। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 8वीं में अध्यनरत नियमित छात्र, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम 'सी' ग्रेड प्राप्त किया है ।

ssmp

एंकर स्टोरी

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को 3 मई तक पैनल तैयार कराने के दिए दिशा-निर्देश

12वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार होगी विषय विशेषज्ञों की पैनल, वाट्सएप पर मिलेगा हर सवाल का जवाब

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर असमंजस बना हुआ है। इस बीच अब विभाग ने बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित होने के संकेत दे दिए हैं। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी बेहतर पढ़ाई कर सकें और उन्हे घर पर ही शैक्षणिक समस्याओं का समाधान हो सके इसके लिए जिलों में विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। जिलों को अपने स्तर पर तीन मई तक विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार करनी होगी। जिलेवार बारहवीं के प्रत्येक विषय के लिए विषय विशेषज्ञों के समूह तैयार होंगे। ज्ञात है कि एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की 30 अप्रैल एवं 1 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को कोरोना के चलते टाल दिया गया है। यह परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह में कराने की बात कही गई थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ऑफलाइन पेपर पेन से जून में भी परीक्षाएं कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि बारहवीं की परीक्षाएं तो अवश्य कराई जाएंगी लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा इस पर चर्चा की जाना है। वहीं दसवीं का मूल्यांकन किस आधार पर कराया जाए इस पर चर्चा होना बाकी है। इस पर कुछ दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा।

भोपाल में 40 विषय विशेषज्ञों की टीम तैयार : राजधानी में 40 विषय विशेषज्ञों की टीम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही वाट्सएप ग्रुप भी बन तैयार हो चुके है। जिनमें अब विषयवार बच्चों को जोड़ा जा रहा है।

हर विषय में चार विशेषज्ञों के पैनल: प्रत्येक विषय में कम से कम चार विशेषज्ञों के पैनल बनाएं जाएंगे। यह पैनल विद्यार्थियों के प्रश्नों एवं समस्याओं का निराकरण करेगा। इसके लिए वाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। वाट्सएप ग्रुप पर विद्यार्थी प्रश्न भेजेंगे। जिनका निराकरण पैनल में शामिल विषय विशेषज्ञ करेंगे। किसी के पास जो भी प्रश्न आएंगे वे उन प्रश्नों के जवाब ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि बार-बार एक ही प्रश्न का उत्तर फिर न बनाना पड़े।

शनिवार से बंद हुई ऑनलाइन पढ़ाई : प्रदेशभर में शनिवार से दसवीं-बारहवीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी कलासों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं एक माह के लिए बंद हो गई है। पहले दिन ही अधिकतर स्कूलों ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर अमल करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी हैं। विभाग का यह आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू किया गया है।

अब विद्यार्थियों के पास एक माह का समय शेष है। ऐसे में अब इस एक माह के समय में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। अगर बच्चों को कोई समस्या है तो वह शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए भोपाल जिले में 40 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। सभी के वाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए है और इन ग्रुप में विद्यार्थियों के नंबर जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है।

नितिन सबसेना
जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर के मुताबिक 25 अप्रैल को आ चुका मप्र में कोरोना का पीक, अब थम गया है

भास्कर न्यूज | भोपाल

ssmp

आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के महामारी के आकलन वाले गणितीय मॉडल 'सूत्र' के मुताबिक मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ चुका है। अब प्रतिदिन नए संक्रमित मरीजों की संख्या 25 अप्रैल को अपने अधिकतम स्तर 13601 पर पहुंचने के बाद लगभग थम गई है। पिछले छह दिन में मामूली उतार-चढ़ाव के साथ नए केसों की संख्या अब कम होना शुरू हो गई है। 30 अप्रैल को प्रदेश में 12400 और 1 मई को 12379 नए संक्रमित सामने आए हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने 30 अप्रैल तक मध्यप्रदेश में लगभग 14500 केस प्रतिदिन नए संक्रमितों की संख्या को पीक माना था। लेकिन 30 अप्रैल से पहले ही मप्र में संक्रमण दर घटती दिखाई देने लगी है। प्रदेश में यह स्थिति तब है जब रोजाना 55 से 60 हजार टेस्ट हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने भी शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आईआईटी कानपुर के नेशनल और स्टेट केस प्रिडिक्शन के अनुसार मध्यप्रदेश अपने कोरोना पीक पर पहुंच गया है। इसलिए अब रोजाना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं।

शासकीय सेवकों को घोषित किया जाए कोरोना योद्धा

जबलपुर. मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने माँग उठाई है कि कोरोना काल में शासकीय सेवकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से कहा है कि संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारियों को ही कोरोना योद्धा घोषित किया गया है। अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी कोरोना के नियंत्रण में ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन किसी तरह की अनहोनी होती है तो उन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का लाभ नहीं मिल पाएगा। संघ के प्रशांत सौंधिया, राजेन्द्र त्रिपाठी, देवेंद्र तिवारी ने कलेक्टर से इस संबंध में आदेश प्रसारित करने की माँग की है। इसी तरह मप्र कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन प्रेषित कर स्थाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की माँग की है। पी-4

पुलिस कर्मियों को मिले अवकाश

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि संघ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, प्रमुख सचिव आदि को एक पत्र प्रेषित कर पुलिस कर्मियों को अवकाश दिए जाने की माँग की है। इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कोरोना काल के दौरान पिछले 14 माह से पुलिस कर्मियों को अवकाश नहीं मिल पा रहा है जिससे वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। संघ के योगेंद्र दुबे, संजय यादव आदि ने पुलिस कर्मियों को सप्ताहिक अवकाश दिए जाने की माँग की है।

ssmp

कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को दी जाएगी पांच लाख की सहायता

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान दिया आश्वासन

भोपाल, (प्रसं)। मध्यप्रदेश में अब कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को तत्काल पांच लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। इस बात पर विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को उनसे मिलने पहुंचे पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान दिया।

ssmp

सीएम ने कहा कि कोरोना से मृत होने वाले पत्रकारों के परिजनों को तत्काल पांच लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी एवं अन्य लोगों की तरह ही पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में घोषित किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर हम निर्णय लेंगे। उन्होंने पत्रकारों के आग्रह पर संचालक जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह के समन्वय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो पत्रकारों के स्वास्थ संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया की पूरी टीम की मेहनत से करोना पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। अब रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। हमने प्रदेश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त कर दी है, टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा कर प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया है साथ ही हमने केंद्र से जो मदद मांगी थी वह भी पूर्ण हुई है। हमने प्लेन से दवाई मंगाई और उन्हें प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने की व्यवस्था की है।

समाज में जागरूकता का माहौल निर्मित करें मीडिया साथी

मुख्यमंत्री ने पत्रकार साथियों से प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा इतनी बड़ी महामारी से निपटने में कुछ अव्यवस्थाएं होती है, लेकिन व्यवस्था बनाने में पूरी टीम रात दिन एक कर रही है। हमें इस नजरिये से देखना चाहिए, लोगों में भय का माहौल निर्मित है,उसे दूर करने की आवश्यकता है, लोगों में कोरोना को लेकर भारी भय का माहौल है, मीडिया के साथी समाज में जागरूकता का माहौल निर्मित करें और लोगों को इस बात से अवगत कराएं की समय रहते अगर सही इलाज हो गया तो कोरोना से कोई भय नहीं है,आईएफजेजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा द्वारा आदिवासी बाहुल्य मंडला में प्रॉपर जांच और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा की मंडला में जल्द ही क्वारंनटाइन सेंटर बढ़ाया जाएगा, साथ ही टेस्ट की व्यवस्था भी बेहतर की जाएगी। मंडला में कोरोना से मृत पत्रकार साथियों के परिजनों को भी पांच लाख की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह, आईएफजेजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मोहन झा, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर एवं सुनील श्रीवास्तव शामिल थे।

कमलनाथ ने भी लिखा सीएम को पत्र

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मीडियाकर्मियों को कोविड-19 योद्धा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है।

860 -
30374

जैन. मो.
मो. नं.
मो. नं.

जिस विभाग का लोक सेवक दिवंगत हो उसे योद्धा योजना की सहायता का भुगतान हो

ssmp

प्रदेश में कर्मचारियों ने कहा तत्काल होना चाहिए कलेक्टरों को आदेश जारी

भोपाल(आरएनएन)। जन सेवा में लगे शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना में संशोधन की मांग उठी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया है।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा एक चिट्ठी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस समय महामारी संक्रमण का बचाव करते हुए नागरिकों की सेवाएं कर रहे हैं। जबकि कुछ विभागों में ही कोरोना योद्धा योजना को लागू किया गया है। इस कारण सरकार को एक संशोधन आदेश जारी करना चाहिए।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ड्यूटी करते हुए यदि कोई लोक सेवक करोना का संक्रमण का शिकार होते हुए दिवंगत होता है तो उसे योद्धा योजना की सहायता सहायता राशि के तत्काल भुगतान होना चाहिए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारी जोखिम उठाकर काम कर रहे हैं। आए दिन दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो रही है। इस कारण इन्हें यह लाभ मिलना चाहिए।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने लिखा पत्र

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें राज्य के समस्त कर्मचारियों को कोविड पॉजिटिव के कारण जनहानि होने पर मुख्यमंत्री कोविड .19 कल्याण योद्धा योजना का लाभ दिये जाने की माँग की गयी है। द्वारा यह बतलाया गया है कि राज्य शासन द्वाराए कोविड .19 प्रभावित रोगियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याणए चिकित्सा शिक्षाए आयुषएनगरीय प्रशासनए गृह विभागए राजस्व विभाग के कर्मचारियो को ही कोविड.19 कल्याण योद्धा घोषित किया गया है। अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों कोई से वंचित किया गया है। ऐसे शासकीय सेवकों को नागरिकों को अपनी सेवाए प्रदान करते हुए कोविड पॉजिटिव होने से जीवन हानि उठानी पड़ी है। इनके आश्रितों को मुख्यमंत्री कोविड.19 कल्याण योजन का लाभ जिले के कलेक्टर द्वारा नही दिया जा रहा है।

हतोत्साहित हो रहे हैं प्रदेश के कर्मचारी

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय मिश्रा का कहना है कि वैश्विक महामारी के दौरान नागरिकों के लिए अपनी सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए इस प्रकार की भेदभावपूर्ण शासन की योजना कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाली है। श्री मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर यह माँग की है कि नागरिकों को अपनी सेवाएं दे रहे जिला तहसील विकास खंड स्तरीय कार्यालयों के समस्त लिपिकीय कार्यपालिक शिक्षक एवं अन्य समस्त संवर्ग के कर्मचारियों के लिए कोविड पाजिटिव के कारण जनहानि होने पर मुख्यमंत्री कोविड .19 कल्याण योजना का लाभ दिये जाने हेतु योजना में आवश्यक संशोधन किये जाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये जाए।

निगम मंडलों में योजना लागू होने के बाद नहीं लाभ

निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव नीलू का कहना है कि इस योजना मे संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि निगम मंडलों में कोरोना योद्धा योजना लागू की गई है। अब जिला स्तर पर कलेक्टर इस योजना का लाभ देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि राज्य स्तर से इस संबंध मे तत्काल एक आदेश जारी होना चाहिए। ताकि समय से दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिल सके।

एसबीआई ने फिर घटाया होम लोन पर ब्याज

30 लाख रुपए तक का होम लोन 6.70 फीसदी पर मिलेगा

मुंबई। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज की दरें फिर घटा दी हैं। 30 लाख रुपए तक का होम लोन अब 6.70 फीसदी ब्याज की दर से मिलेगा। अगर होम लोन 30 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको 6.95 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होगा। बैंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। बैंक ने कहा कि 6.95 फीसदी की दर 30 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर लागू रहेगी। अगर लोन 75 लाख से ज्यादा है तो फिर ब्याज दर बढ़कर 7.05 फीसदी हो जाएगी। अगर आप इसके बैंकिंग ऐप योनो से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पांच बीपीएस की छूट और मिलेगी। एसबीआई के रिटेल और डिजिटल बैंकिंग के प्रबंध निदेशक सीएस शेट्?टी ने कहा कि होम फाइनेंस में एसबीआई एक मार्केट लीडर है और होम लोन मार्केट में ग्राहकों के सेंटीमेंट को देखते हुए ब्याज दरों को कम रखा जाता है। हमें विश्वास है कि यह नया फैसला होम लोन लेने वालों और रियल इस्टेट इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छा होगा। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में बैंक ने अपनी होम लोन की ब्याज दरें घटाकर 6.70 फीसदी कर दी थी। यह 31 मार्च तक के लिए थी और अप्रैल में बैंक ने फिर से इसे बढ़ाकर 6.95 फीसदी पर कर दिया था। पर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए और बैंकिंग इंडस्ट्री में पहले से ही कुछ कम दरों के चलते बैंक ने फिर से इसे पुरानी दर पर ला दिया है।

ssmp

प्रदेश में लोगों को तनाव मुक्त बनाने के लिए निशुल्क योग प्रशिक्षण

ssmp

आर्ट ऑफ लिविंग का शौर्य अभियान

भोपाल (आरएनएन)। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर पद्मविभूषण श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा समूचे मप्र में सभी के लिए निःशुल्क योग प्रशिक्षण अभियान 'चलाया जा रहा है।

प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, रोजगार भी प्रभावित होने से एक बड़ा वर्ग निराशा के दौर में जी रहा है, साथ ही कोविड महामारी से पीड़ित जनों तथा उनके परिवार का संतुलन डगमगाया हुआ है .गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति किसी युद्ध से कम नहीं है और इससे जीतने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के शौर्य को जागृत करने की आवश्यकता है। इस लिये सभी मानसिक तनाव ग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिये चलाये जा रहे इस अभियान को शौर्य कहा गया है। प्रदेश में आर्ट ऑफ लिविंग के 400 प्रशिक्षक प्रदेश के अलग-अलग सभी जिलों में एक साथ शौर्य अभियान के संचालन में जुट गए हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम का यह अभियान ऑनलाइन होगा जिसमें हर व्यक्ति शामिल होकर तनाव मुक्त हो सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग के स्टेट मीडिया को-ऑर्डिनेटर और योग प्रशिक्षक ऋतुराज असाटी ने बताया कि तीन दिवसीय शिविर में इस दौर में बढ़ रही निराशा और भय जैसी भावनाओं को दूर कर मन की स्थिति को दृढ़ और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को तीव्र बनाने के साथ साथ कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों के मनोभावों की देखभाल और स्वस्थ होने के बाद उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ पर कार्य होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षकों द्वारा इस संबंध मे जनसंपर्क किया जा रहा है।

संकट में अवसर : श्री असाटी के अनुसार गुरुदेव ने कहा है कि कोरोना काल में छोटे बड़े व्यापार या निजी नौकरीपेशा लोग काफी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, जिससे उनके परिवार भी अछूते नहीं हैं । इस कारण लोगों को अपने मन को दुर्बल होने से नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि संकट के समय चारों ओर नकारात्मक बातें ही अधिक दिखाई और सुनाई देती हैं, इससे व्यक्ति शीघ्र ही तनाव से घिर जाता है। हमें हर संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए । यह समस्या नया सृजन लेकर आई है और इससे निपटने के लिए हमें अपने अंदर छिपे शौर्य को बाहर निकालना चाहिए। यह योग प्रशिक्षण कार्यक्रम यही बताने के लिये है कि हम इन हालातों में अपने आप को कैसे तनाव से दूर रखें और नई ऊर्जा के साथ फिर से सृजन में लगें । लॉकडाउन में घरों में बैठे बहुत से लोग नीरसता और भय से उपजे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वे इस तनाव से दूर रहने के लिए योग को एक सरल एवं अच्छे साधन के रूप में अपना सकते हैं । लोगों को योग और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए तथा कुछ समय ध्यान अवश्य करना चाहिए ।

लोगों से बात करनी चाहिए : श्री श्री रवि शंकर ने कहा कि कोरोना संकट में हजारों-लाखों लोग सड़कों पर हैं, परेशान हैं, भूखे-प्यासे हैं ऐसे में हमें जरूरतमंद लोगों की अपने अपने स्तर से मदद जरूर करनी चाहिए। परेशान लोगों से बात करनी चाहिए। उन्हें सांत्वना देनी चाहिए।

सकारात्मक बातों पर ध्यान दें : तनाव के कारण लोगों का मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है. लोग डिप्रेशन, चिंता, अतिशय भय, अकारण क्रोध जैसी कई मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हो रहे हैं. ऐसे में तनाव से बचने के लिए हमें नकारात्मक बातों को त्याग कर सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। घर के कामों में सहयोग करना चाहिए, घर के सदस्यों को आपस में बात करनी चाहिए और जो काम आप सामान्य दिनों में समय की कमी के चलते नहीं कर पा रहे थे, उन्हें करना चाहिए।

कोरोना में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को 50 बेड आरक्षित किए जाएं

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए संक्रमण होने पर अस्पतालों में पलंग उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा जाएगा।

ssmp

कर्मचारी लिखेंगे मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी समिति के प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी एवं मध्यप्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगो को यदि कोरोना हो जाये तो इस महामारी में लोगो को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। वहीं कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी के परिजनों को तत्काल उनके लिए बेड मिलना चाहिए और इलाज में यदि आवश्यक हो तो रेमेडीसीवीर या अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होना चाहिए।

इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंप कर उनसे मांग करेंगे कि तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन को कोरोना में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए कम से कम 50 बेड ऑक्सीजन एवं जीवन रक्षक दवाओं के साथ आरक्षित किये जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएं। ताकि कर्मचारी निडर होकर अपनी सेवाएं कोरोना में देते रहे और उन्हें परिजनों के बीमार होने की स्थिति में परेशान न होना पड़े। उन्होंने बताया कि अन्य जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। इस कारण भोपाल में भी इसी प्रकार के प्रबंध होना चाहिए।

मनाही के बाद भी दिव्यांग कर्मचारियों को जबरन ड्यूटी पर बुला रहे अफसर

विधि विभाग में 16 अधिकारी कर्मचारी पॉजिटिव, 2 की हो चुकी मौत

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

ssmp

राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विकलांग शासकीय सेवकों को ऐसे समय में कार्यालय ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। उसके बाद भी विभाग प्रमुख बेरोकटोक दूरभाष पर निर्देश देकर इन मैप लोक सेवकों को कार्यालय बुला रहे हैं। पिछले महीने जब कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाना ने शुरू किया था तो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके अनुसार सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की 10 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। उसके बावजूद कई विभाग तो 50 प्रतिशत अनुपात के हिसाब से कर्मचारियों को बुला रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा में सप्ताह पहले इस संदर्भ की शिकायत हुई थी। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण में भी 50 प्रतिशत उपस्थिति का विरोध किया गया था। यह समस्या निपटी नहीं है कि अधिकारियों ने दूसरी परेशानी पैदा कर दी है। गाइडलाइन का पालन ना करते हुए समस्त विभागों में अधिकारी और कर्मचारी दिव्यांग लोक सेवकों को कार्यालय में ड्यूटी करने के लिए बुला रहे हैं। आर्थिक सांख्यिकी संसदीय कार्य कृषि कल्याण आयुष सहित अनेक ऐसे विभाग हैं जहां पर दिव्यांग कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग भी इस विषय में पहले कह चुका है कि संक्रमण का अधिक खतरा को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों में सिर्फ 10 प्रतिशत मौजूदगी हो। इसके अलावा अभी दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय ना बुलाया जाए। कई महिला दिव्यांग कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है कि अधिकारी फोन करके ऑफिस बुलाने का दबाव डाल रहे हैं।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष अनिल एडविन का कहना है कि सभी विभागों में सरकार की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। ताकि नियम से सरकारी लोकसेवक शासन के आदेश का पालन कर सकें। इसके अलावा वह अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें।

विधि विभाग में 16 अधिकारी कर्मचारी हुए पॉजिटिव

विंध्याचल में संचालित विधि विभाग में 16 अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी है कि यहां कर्मचारियों की लगातार शत.प्रतिशत मौजूदगी के बाद यह हालात निर्मित हुए हैं। कर्मचारी शुरू से ही शिकायत करते रहे हैं कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार 10 फीसदी उपस्थिति ही कर्मचारियों की दर्ज करवाई जाए लेकिन अधिकारी नहीं माने जिसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि संक्रमण का अधिक खतरा बढ़ने के कारण यहां पर 2 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। विधि में यह हालत निर्मित होने से नजदीक लगने वाले अन्य विभागों में भी दहशत का माहौल है।

आदेश की स्थिति स्पष्ट करे राज्य की सरकार

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग कोरोना योद्धा की के आदेश की स्थिति को स्पष्ट करें। हाल ही में विभाग की प्रमुख सचिव द्वारा एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कोरोना योद्धा योजना के आदेश की कंडिका में शिक्षकों को भी लाभ देने का प्रावधान है। श्री श्रीवास्तव का कहना है कि विभाग को यह स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि कोरोना संक्रमण से लड़ने में सबसे अधिक जन सेवा का कार्य शिक्षा विभाग के लोक सेवक कर रहे हैं।

वैक्सीनेशन कराए बिना ही लगा दिया कर्मचारियों को ड्यूटी में

खाद्य एवं आपूर्ति निगम सहित कई विभागों ने जनवरी में ही कर दिए थे आदेश

ssmp

भोपाल ■ राज न्यूज़ नेटवर्क

बिना वैक्सीनेशन कराए कोरोना ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों पर लगातार संक्रमण का आक्रमण हो रहा है। जबकि कई विभागों द्वारा जनवरी माह के अंत में ही कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए थे कि समस्त लोक सेवकों का अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाया जाए।अब हालात यह है कि बिना वैक्सीन का टीका लगवा कर काम कर रहे कर्मचारी अधिकारी आए दिन कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।

बताना होगा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के कमिश्नर तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा इस संबंध में जनवरी माह नहीं सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए थे। इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा है। इस कारण जिलों में सभी अधिकारी और कर्मचारियों का शिविर लगाकर वैक्सीनेशन करवाया जाए।

विभाग ने हाल ही में इस बात पर चिंता भी जाहिर की है कि कलेक्टरों को सख्त आदेश जारी करने के बाद भी इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों की कोरोना में ड्यूटी लग रही है। यदि वैक्सीन पहले ही लग जाती तो निश्चित तौर पर ऐसे लोकसेवक कोरोना संक्रमण से बच सकते थे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी इस संदर्भ में पिछले महीने आदेश जारी किए गए थे लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

जिला स्तर पर नहीं दी गई वैक्सीन की कोई खुराक

शिक्षा विभाग में अध्यापकों एवं शिक्षकों की सेवाएं तो समय समय पर कोरोना महामारी के समय ली गई परंतु इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा प्रदान नही किया गया। जिसके कारण न तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन के दोनों खुराक मिले और न ही इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा प्राप्त हुआ। और यह संवर्ग लगातार अपनी सेवाएं देता रहा। जिसके कारण मध्यप्रदेश में हजारों शिक्षक न केवल संक्रमित हुए बल्कि सैकड़ों की असमय मृत्यु हो गई। अभी इन्हें लॉक डाउन के समय शहर की सीमाओं पर बनाये गए नाकों पर भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। दिक्कत तब प्रारंभ हुई जब शिक्षकों को घर घर जाकर संक्रमित व्यक्तियों के सर्वे के लिए ड्यूटी में लगा दिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित करने वाले मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि शिक्षकों को बिना पूर्ण वैक्सिनेशन और बिना कोरोना योद्धा का दर्जा प्रदान किये इस तरह की ड्यूटी में लगाना सीधा सीधा इस भीषण महामारी की चपेट में ढकेलना है। इससे जहाँ एक ओर पूरे अध्यापक शिक्षक संवर्ग में मानसिक तनाव और भय का वातावरण तैयार हो गया है। वही दूसरी तरफशासन के प्रति भी नकारात्मक धारणा बन रही है। क्योंकि अध्यापक से शिक्षक बने संवर्ग के आश्रितों को न तो जीवन यापन लायक पेंशन मिलेगी और न ही सरलता से अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ मिलना संभव दिख रहा है।

ड्यूटी करने में नहीं है कर्मचारियों को कोई दिक्कत

मध्य प्रदेश शिक्षक संगठन के प्रदेश सचिव राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार को कोरूना ड्यूटी कर रहे सभी विभागों के कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि हमें किसी भी प्रकार की ड्यूटी करने में दिक्कत नहीं है। परंतु पहले हमें कोरोना योद्धा का दर्जा और सुरक्षा प्रदान की जावे। ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी का विपरीत प्रभाव हमारे परिवार पर न पड़े। अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग को भी कोरोना योद्धा का दर्जा एवं सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग उन्होंने की है।

शुरू करें एसआईपी, बेहतर रिटर्न के साथ मिलेगा 50 लाख तक का मुफ्त इंश्योरेंस

बिजनेस डेस्क

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट में जहां लोगों की बचत करने की आदत में इजाफा हुआ है, वहीं, इंश्योरेंस की मांग भी पिछले 1 साल में खूब बढ़ी है। कोरोना संकट में बहुत से लोग सीधे इक्विटी में निवेश करने की बजाए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश का प्लान कर रहे हैं, वहीं, बहुत से लोग कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहे हैं। पर इन दिनों ये दोनों काम एक ही प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है। असल में कोरोना क्राइसिस को देखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां एसआईपी के साथ इंश्योरेंस कवर फ्री में दे रही हैं। इंश्योरेंस कवर एसआईपी की रकम और टेन्योर के आधार पर तय हो रही है।

ये फंड हाउस कर रहे आफर

देश की कुछ दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउस ने एसआईपी के साथ मुफ्त बीमा कवर का लाभ देना शुरू किया है। जिन एसआईपी में बीमा कवर का भी लाभ दिया जा रहा है उनमें पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एसआईपी इंश्योरेंस और आदित्य बिड़ला सनलाइफ सेंचुरी एसआईपी प्रमुख हैं। अगर निवेशक इन फंड हाउस के एसआईपी प्लान के साथ निवेश शुरू करते हैं तो उनको बिना मेडिकल जांच के इंश्योरेंस का लाभ मिलना शुरू होगा।

- कोरोना संकट में म्यूचुअल फंड कंपनियां दे रही है आफर
- कोरोना क्राइसिस को देखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां लाई नई योजना

क्या है आफर

यह एक फ्री इंश्योरेंस कवर है, जिसके लिए एसआईपी शुरू करते समय कोई भी विकल्प चुन सकता है। यह ज्यादातर फंड हाउस की सभी इक्विटी और हाइब्रिड योजनाओं पर दिया जा रहा है। अधिकांश फंड हाउस प्रतिनिधित्व उद्योग में निवेश करने वाले 18-51 आयु वर्ग के लोगों को एसआईपी बीमा दे रहे हैं। इसके तहत किसी तरह के मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये शुद्ध इंश्योरेंस पॉलिसी है। 55 साल की आयु तक बीमा कवर मान्य है। इसलिए, अगर कोई निवेशक 51 साल की उम्र में 10 साल का एसआईपी शुरू करता है, तो बीमा कवर 55 साल की उम्र तक उपलब्ध होगा। हालांकि कुछ कंपनियां 60 साल की उम्र तक भी आफर दे रही हैं।

अतिथि शिक्षकों की सेवाओं में की गई वृद्धि

रीवा(नव स्वदेश)। प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवायें 30 अप्रैल 2021 के बाद भी ली जा सकेंगी। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं संपादित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यो को इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया गया है।

ssmp

लाकडाउन में बच्चों की बढ़ रही पौराणिक कथाओं में रुचि

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। एक वार फिर सभी कोरोना संक्रमण के खतरे से वचने के लिए लाकडाउन के चलते अपने-अपने घरों में है। ये लाकडाउन पिछली वार की तुलना में थोड़ा अलग है। पिछली वार सभी के लिए सभी कुछ नया था। पर इस वार सभी को पता है कि क्या- क्या करना है। अव इसी रूटीन में से कुछ नया क्या हो सकता है इसकी कोशिश में सभी लगे हुए हैं। पिछले लाकडाउन में नई पीढ़ी के वच्चों ने रुचि लेकर रामायण देखी थी। कुछ वच्चों पर रामायण का वहुत असर हुआ है। जो एक साल वाद भी उन्हें पौराणिक कथाओं से जोड़े हुए है। इसके लिए वच्चों ने घर में मौजूद रामायण, गीता के साथ अन्य कथाओं को पढ़ना भी शुरू कर दिया है। नवमीं क्लास के छात्र ऋषि वर्मा ने वताया कि उन्होंने पिछले लाकडाउन में भी हर दिन थोड़ी-थोड़ी रामायण पढ़ी थी और इस समय भी पढ़ रहे हैं। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था पर जव समझ कर पढ़ना शुरू किया तो समझ में भी आने लगा। इसी तरह कंचन ठाकुर जो कि 10 वीं की छात्रा हैं उन्होंने इंटरनेट पर डिवाइन टेल्स में कहानियां पढ़ना और देखना शुरू की

वच्चों ने घर में मौजूद रामायण, गीता के साथ अन्य कथाओं को पढ़ना भी शुरू कर दिया है। ● इंटरनेट मीडिया

थी। जो पूरे साल जारी रखा। इसे देख कर कई अच्छी वातें सीखी और कई नियमों को अपने जीवन में शामिल भी किया। वाल भवन के संचालक गिरीश विल्लोरे ने वताया कि वीते दिनों में वच्चों में अपनी पौराणिक कथाओं को जानने की रुचि वढ़ी है। मुझसे कई वच्चों ने आकर खुद से रामायण के वारे में चर्चा भी की है। यह एक अच्छी वात है कि वच्चे ऐसा कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि जव रामायण आती थी तो वच्चे न सिर्फ उसे देखते थे वल्कि घर पर रामायण के वारे में वातें भी करते थे। ये समय कठिन है पर वच्चों में जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं वो वहुत अच्छे हैं। नई पीढ़ी को इन संस्कारों की जरूरत है। इसे देने की जिम्मेदारी माता-पिता की ही है। सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। घर पर वच्चों को जैसा माहौल देंगे वैसे ही संस्कार वच्चों में आएंगे।

प्रयास | टीका लगने के बाद मौत हो जाने की अफवाह के चलते ग्रामीण नहीं लगवा रहे टीका

टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ में झाड़-फूंक वालों की लेंगे मदद

मोहम्मद इमरान खान • जगदलपुर

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला प्रशासन नया प्रयोग करने जा रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी तामझाम के साथ सिरहा-बैगाओं को फ्रंटलाइन में लाया जा रहा है। यह टीकाकरण पर ग्रामीणों का विश्वास जगाने का काम करेंगे। अबूझमाड़ समेत पहुंच से दूर गांवों में जहां स्वास्थ्य सेवा का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता, वहां सिरहा-बैगा झाड़-फूंककर ग्रामीणों का इलाज करते हैं। ग्रामीण आज भी इन पर बहुत विश्वास करते हैं। प्रशासन इसका लाभ उठाने की तैयारी में है।

दरअसल, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद मौत होने की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने कुछ जगहों पर स्वास्थ्य अमले को टीका लगाने से रोककर बैरंग लौटा दिया है। माड़ के झारवाही में भी इस प्रकार का मामला सामने आया है। कोरोना वैक्सीन के साथ ग्रामीण अब बच्चों के सामान्य टीके लगवाने से भी पीछे हट रहे हैं। इससे टीकाकरण करने जा रही मितानिनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मानें तो गांव में कोई बीमार होता है तो वे सबसे पहले सिरहा-बैगा के पास ही जाते हैं। अशिक्षित ग्रामीणों का समूह छोटी-बड़ी बीमारी पर इनके पास जाता है। सिरहा-बैगा कोरोना के साथ जारी जंग में मददगार बनते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकता है।

नारायणपुर में हो चुका है बड़ा सम्मेलन

अबूझमाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक दशक पूर्व सिरहा-बैगाओं का बड़ा सम्मेलन नारायणपुर में कराया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के उस कार्यक्रम में अबूझमाड़ के करीब 300 सिरहा-बैगाओं ने भाग लिया था। मौसमी बीमारी के दौरान झाड़-फूंक कराने आने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों तक भेजने की अपील की गई थी, जिसका [illegible] में मिला।

ssmp

> टीकाकरण के लिए सिरहा-बैगाओं को प्रोत्साहित करने की तैयारी चल रही है ताकि गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके।
>
> - धर्मेश साहू
> कलेक्टर, नारायणपुर

आदिवासी सिरहा-बैगा पर करते हैं बहुत भरोसा, इसके चलते प्रशासन करेगा प्रयोग

छत्तीसगढ़ में 12 महीनों पर अकेले भारी पड़ा अप्रैल

रायपुर | नईदुनिया प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला लगभग 13 महीने पहले 18 मार्च 2020 को सामने आया था, लेकिन अप्रैल 2021 में कोरोना ने जितना कहर बरपाया है, उतना उसके पहले के 12 महीनों में नहीं बरपाया था। राज्य में पहली बार एक दिन में मिलने वाले नए केस का आंकड़ा 10 हजार के पार भी इसी माह पहुंचा। अप्रैल में पाजिटिविटी दर यानी जांच कराने वालों में संक्रमित मिलने वालों का औसत 32 तक पहुंच गया। रिकवरी रेट (ठीक होने वाले मरीजों की संख्या) 74 तक गिर गई थी, जबकि अप्रैल की शुरुआत में यह 90 फीसद तक था। इस स्थिति में सुधार आया है, लेकिन मृत्यु दर अभी राष्ट्रीय स्तर 1.12 से अधिक है।

स्कूल शिक्षा मंत्री की पहल पर शुरू हुआ कोविड सेंटर

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल

editor@peoplessamachar.co.in

स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार की पहल पर शाजापुर जिले में शुरू किए गए अपनों के लिए-अपना कोविड सेंटर के बेहतर परिणाम आने लगे हैं। इस सेंटर में भती 327 मरीजों में से अब तक 208 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।

समाज के सहयोग से शासन लारा संचालित 150 बिस्तरों वाले अपनों के लिए-अपना कोविड सेंटर में मरीजों के लिए सभी आवश्यक और बुनियादी आवश्यकताएं जैसे बेड, कूलर, टीवी आदि के साथ ही नाश्ता, चाय, दोनों समय के भोजन की पूरी सुविधा है। गांव के युवा कोरोना वॉरियर बन मरीजों की देखभाल में लगे है।

अपनों के लिए.अपना कोविड सेंटर को संचालित करने के लिए समाज के सभी वर्गों ने अपनी क्षमता और सेवाभाव अनुसार वस्तुएं दान की हैं। शाजापुर और आगर मालवा जिले के प्रभारी मंत्री परमार कोरोना संक्रमण के रोकथाम और प्रबंधन के लिए सतत और निरंतर कार्यरत हैं।

विधायक निधि से दिए 50 लाख

कोरोना काल में मंत्री इन्दर सिंह परमार ने अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार, व्यवस्थाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हाई प्रेशर मशीन के क्रय के लिए प्रशासन को उपलब्ध कराये हैं।

पत्रकारों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने पीएम से की मांग

एनयूजेआई, एडिटर्स गिल्ड ने मोदी को लिखा खत

एजेंसी ● नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

ssmp

पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडियाकर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने तथा उनके त्वरित टीकाकरण किए जाने एवं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है।

एनयूजे-आई के अध्यक्ष रास बिहारी ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को भेजे एक पत्र में कहा है कि मीडिया कर्मियों ने कोरोना महामारी के संदर्भ में जनजागरूकता अभियान में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काम के बीच देशभर में कोरोना से संक्रमित मीडियाकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक तौर पर कमजोर होने के कारण बड़ी संख्या में पत्रकार उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं। देश में कोरोना के कारण दो सौ से अधिक पत्रकारों की जानें जा चुकी हैं। रास बिहारी ने कहा कि पिछले एक वर्ष से जारी कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह ही मीडियाकर्मी भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अखबार और चैनल जनता को महामारी से बचने के उपायों की जानकारी देने के साथ ही तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

300 रु. विलंब शुल्क के साथ तीन तक बीबीए में कर सकेंगे आवेदन

इधर, यूजी-पीजी में आवेदन का कल आखिरी दिन

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

ssmp

बरकतउल्ला विवि की बीबीए, होटल मैनेजमेंट प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की तारीख समाप्त हो गई है। अब स्टूडेंट 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे।

वहीं यूजी-पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए भी सामान्य शुल्क के साथ 3 मई तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा सभी सेमेस्टर एवं ईयर के ओपन बुक एग्जाम के आदेश जारी किए गए हैं। बीयू द्वारा उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह संसोधित तारीखें जारी की गई थीं। बीयू द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की संशोधित तारीख के अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, होमसाइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम आनर्स के स्टूडेंट पात्रतानुसार एमपी ऑनलाइन से आवेदन कर सकेंगे। विशेष विलंब शुल्क 1000 रुपए के साथ 4 मई से परीक्षा शुरू होने से तीन दिन पूर्व तक आवेदन किया जा सकेगा।

12वीं की परीक्षा: स्कूल शिक्षा विभाग ने डीईओ को विशेषज्ञों की पैनल बनाने के दिए निर्देश

वॉट्सऐप से परीक्षा की तैयारी कराएंगे टीचर

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893232137

माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की 12वीं की परीक्षाएं जून के प्रथम सप्ताह में होना है। ऐसे में स्टूडेंट्स की पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए विषय विशेषज्ञों की पैनल बनाई जा रही है। टीचर वॉट्सऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स के प्रश्नों का जवाब देकर उनके डाउट क्लीयर करेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 12वीं की परीक्षाएं हर हाल में आयोजित की जाएंगी। कोरोना सक्रंमण के बीच इसका पैटर्न क्या हो, इस पर विचार- विमर्श किया जा रहा है। 12वीं के विद्यार्थी बेहतर पढ़ाई कर सकें और उन्हें घर पर ही शैक्षणिक समस्याओं का समाधान मिल सके, इसके लिए जिलों में विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार करने

के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। जिलों को अपने स्तर पर तीन मई तक विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार करनी होगी। जिलेवार बारहवीं के प्रत्येक विषय के लिए विषय विशेषज्ञों के समूह तैयार होंगे। ज्ञात कि एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 30 अप्रैल एवं 1 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को कोरोना के चलते टाल दिया गया है। परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह में कराने की बात कही गई थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ऑफलाइन पेपर पेन से जून में भी परीक्षाएं कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि 12वीं की परीक्षाएं तो अवश्य कराई जाएंगी, लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा, इस पर चर्चा की जानी है। वहीं दसवीं का मूल्यांकन किस आधार पर कराया जाए, इस पर भी चर्चा होना बाकी है। इस पर कुछ दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा।

अब विद्यार्थियों के पास एक माह का समय शेष है। अगर बच्चों को कोई समस्या है, तो वह शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए भोपाल जिले में 40 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। सभी के वाट्सऐप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इन ग्रुप में विद्यार्थियों के नंबर जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। **नितिन सक्सेना,** जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल।

राजधानी में 40 विषय विशेषज्ञों की पैनल तैयार की जा रही

भोपाल में 40 विषय विशेषज्ञों की टीम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही वाट्सऐप ग्रुप भी बनाए जा चुके हैं, जिनमें अब विषयवार बच्चों को जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक विषय में कम से कम चार विशेषज्ञों के पैनल बनाएं जाएंगे। यह पैनल विद्यार्थियों के प्रश्नों एवं समस्याओं का निराकरण करेगा। इसके लिए वाट्सऐप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। वाट्सऐप ग्रुप पर विद्यार्थी प्रश्न भेजेंगे, जिनका निराकरण पैनल में शामिल विषय विशेषज्ञ करेंगे। किसी के पास जो भी प्रश्न आएंगे, वे उन प्रश्नों के जवाब ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि बार-बार एक ही प्रश्न का उत्तर फिर न बनाना पड़े।

ssmp

सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 20 जून को, बोर्ड ने तय किया एसेसमेंट का फॉर्मूला

चेतावनी : भेदभावपूर्ण एसेसमेंट करने पर स्कूलों पर लगेगा जुर्माना

एजेंसी ● नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

ssmp

सीबीएसई दसवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून तक जारी होंगे। यह परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। रिजल्ट के लिए शनिवार को अंक निर्धारण नीति की घोषणा की गई। इसके अनुसार हर विषय में हर साल की तरह 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन, जबकि 80 प्रतिशत अंक पूरे वर्ष के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान किए गए अंक 10वीं की पिछली बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के प्रदर्शन के अनुरूप हों। रिजल्ट को अंतिम रूप देने के लिए स्कूलों को 8 सदस्यीय परिणाम समितियों का गठन 5 मई करना होगा। मूल्यांकन में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने में संलिप्त स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उनकी संबद्धता रद्द कर दी जाएगी।

जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, उनका फोन पर या ऑनलाइन असेसमेंट

बोर्ड ने बताया कि जो स्टूडेंट्स पूरे साल पर्याप्त टेस्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके लिए स्कूल 15 मई तक ऑनलाइन या टेलीफोन पर आकलन करेंगे और उन्हें 25 मई तक परिणाम को अंतिम रूप देना होगा। नियंत्रक ने कहा कि सीबीएसई को 11 जून तक अंक सौंपे जाने हैं और 20 जून तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

संकलन
धीरेंद्र कुमार पांडेय
शासकीय हाई स्कूल चचाई
9407888988